शिक्षक पोर्टल एवं नवाचार समूह
मध्यप्रदेश

दसवीं-बारहवीं की परीक्षा टालने के बाद अब प्रायोगिक परीक्षा स्थगित

बीस मई तक होना थी प्रायोगिक परीक्षा, कोरोना कर्फ्यू के चलते टाली गई परीक्षाएं

शहर प्रतिनिधि, भोपाल। मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की दसवीं-बारहवीं की बोर्ड परीक्षा एक महीने टालने के बाद अब प्रायोगिक परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। यह परीक्षाएं बीस मई तक होना थी। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए हैं।

माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 10वीं-12वीं, डिप्लोमा इन प्री एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा पत्रोपाधी की प्रायोगिक परीक्षाएं 17 अप्रैल से 20 मई के बीच कराने के निर्देश दिए थे। राज्य में पंद्रह मई तक कोरोना कर्फ्यू (लॉकडाउन) है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण भी तेजी से फैल रहा है। इस कारण प्रायोगिक परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। स्थगित प्रायोगिक परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में तिथियां अलग से घोषित की जाएगी। इससे पहले 10वीं की परीक्षा 30 अप्रैल और 12वीं की परीक्षा 1 मई से शुरू होने थी, लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं परीक्षा को एक महीने के लिए टालने का फैसला किया है। इसमें प्रदेश भर से करीब 19 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे।

सीबीएसई की तर्ज पर दसवीं के विद्यार्थियों को नहीं मिलेगा जनरल प्रमोशन

मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की दसवीं बोर्ड की परीक्षा पर असमंजस बरकरार है। हालांकि दसवीं बोर्ड के छात्रों की परीक्षा निरस्त हो गई है, लेकिन छात्रों को पास करने के स्वरूप पर विभाग अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाया है। हालांकि अब सिर्फ बारहवीं की परीक्षा होगी। दसवीं के विद्यार्थियों को एमपी बोर्ड द्वारा सीबीएसई की तर्ज पर जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। विभागीय मंत्री इंदर सिंह परमार पूर्व में स्पष्ट कर चुके है कि दसवीं के विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए मापदंड पर विचार किया जा रहा है। विभागीय सूत्रों की मानें तो नियमित विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर नंबर दे दिए जाएंगे, जबकि प्राइवेट विद्यार्थियों की परीक्षा करा ली जाए। इस पर हल नहीं निकलने पर सभी छात्रों को जनरल प्रमोशन देने का विकल्प भी खुला हुआ है।

नवमीं-ग्यारहवीं की परीक्षाओं का पंद्रह मई तक नहीं आएगा परिणाम

कोरोना वायरस महामारी में बढ़ोतरी के कारण स्कूल शिक्षा विभाग ने कक्षा नवमीं और ग्यारहवीं की फाइनल परीक्षाओं को रद्द कर चुका है। कक्षा 9 वीं और 11वीं के छात्रों का नवंबर में मूल्यांकन किया गया था। इसमें तिमाही परीक्षा के रूप में रिविजन टेस्ट व छमाही परीक्षा ली गई थी। इसकी दोनों परीक्षाओं के केवल परफार्मेंस के आधार पर दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर रिजल्ट तैयार किया जा रहा है विभाग के अधिकारियों के अनुसार नवमीं के फाइनल परिणाम पांच विषयों में से सर्वश्रेष्ठ के आधार पर जारी किए जाएंगे। यदि वे पांच विषयों में पास होते हैं और कुल छह विषयों में से एक विषय में फेल हो जाते हैं, तो उन छात्रों को पास घोषित किया दिया जाएगा। एक से अधिक विषयों में 33 फीसदी अंक प्राप्त करने में असफल रहने वाले छात्रों के लिए, अधिकतम 10 ग्रेस मार्क्स अंक प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा 9 वी और कक्षा 11 वी परीक्षाओं के लिए उपस्थित होने का अवसर भी उन छात्रों को प्रदान किया जाएगा, जो फाइनल परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक अंक प्राप्त करने में असमर्थ है। इसके अलावा जो छात्र सितंबर-नवंबर 2020 या फरवरी की परीक्षा में शामिल नहीं हो सके है, उन्हें परीक्षा के लिए उपस्थित होने का एक और मौका दिया जाएगा। यह मौका कोविड 19 से उत्पन्न स्थिति में सुधार होने के बाद दिया जाएगा। विभाग द्वारा पंद्रह मई तक परिणाम घोषित करने की तिथि रखी है। हालांकि कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए रिजल्ट पंद्रह मई तक जारी होने की संभावना कम है। रिजल्ट 31 मई तक घोषित किए जाने की संभावना है।

एमपी बोर्ड : 10वीं व 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम भी स्थगित

भोपाल। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए एमपी बोर्ड द्वारा 10वीं-12वीं की थ्योरी एग्जाम जून तक टाल दिए गए हैं, अब प्रैक्टिकल एग्जाम भी स्थगित कर दिए गए हैं। यह एग्जाम 20 मई तक होने थे। इस संबंध में एमपी बोर्ड ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी आदेश में कहा गया, राज्य में 15 मई तक कोरोना कर्फ्यू है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण भी तेजी से फैल रहा है। इस कारण प्रायोगिक परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है।

एजुकेशन पोर्टल पर मिलेगी शिक्षकों व स्टाफ की डिटेल

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल

मो.नं. 9893231237

स्कूल शिक्षा एवं आदिम जाति कल्याण विभाग में कार्यरत सभी शिक्षकों व गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की पूरी जानकारी एजूकेशन पोर्टल पर पे-रोल एवं ई-सर्विस बुक प्रणाली से ऑनलाइन दर्ज की गई है। प्रत्येक लोक सेवक अपने आईडी पासवर्ड से इस जानकारी को देखेगा और जरूरत पड़ने पर समय-समय पर संकुल प्राचार्य या अधिकारी अपग्रेड करेंगे। लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों एवं परियोजना समन्वयकों के साथ आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयक्त व जिला संयोजकों को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि पदोन्नति, स्थानांतरण, संविलियन, युक्तियुक्तकरण, पदक्रम सूची निर्धारण, गोपनीय चरित्रावली संधारण, अनुशासनात्मक कार्रवाई आदि सभी कार्य ऑनलाइन किए जाएंगे। ताकि प्रत्येक शिक्षक व कर्मचारी की जानकारी सुचारु बनी रहे। वहीं सेवानिवृत्ति, बर्खास्तगी, त्यागपत्र या मौत होने पर स्टॉप पेमेंट पर्मानेंट आप्शन से शिक्षकों का नाम सूची से हटाया जाएगा। इसी तरह निलंबन होने पर स्टॉप पेमेंट टेम्परेरी आप्शन से पोर्टल पर जानकारी दर्ज होगी।

सीबीएसई स्कूलों में 15 से 20 प्रतिशत तक हुए एडमिशन, लेकिन एमपी बोर्ड के स्कूलों में अभी तक जीरो

शीघ्र कम नहीं हुआ कोरोना तो यह सत्र भी हो जाएगा जीरो

पीपुल्स संवाददाता • भोपाल
मो.नं. 9893231237

कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल-कॉलेज बंद हैं, ऐसे में पिछले सत्र में अधिकांश स्कूलों में एडमिशन शून्य थे, इस बार भी स्कूलों में वही स्थिति है। राजधानी के सीबीएसई स्कूलों में जनवरी से एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने के कारण 15 से 20 प्रतिशत ही एडमिशन हुए हैं, लेकिन एमपी बोर्ड प्राइवेट व सरकारी स्कूलों में तो एडमिशन शुरू भी नहीं हुए। ऐसे में यदि शीघ्र ही कोरोना नियंत्रित नहीं होता, तो यह सत्र भी जोरी ही जाएगा। आमतौर पर सीबीएसई स्कूलों में जनवरी से नए सत्र के लिए एडमिशन शुरू हो जाते हैं। ऐसे में राजधानी के सहोदय ग्रुप के सभी स्कूलों में जनवरी

व फरवरी में 15 से 20 प्रतिशत स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया है। उसके बाद कोरोना संक्रमण बढ़ा और स्कूल बंद होने के साथ ही एडमिशन प्रक्रिया रोक दी गई है। इन स्कूलों ने पिछले वर्ष मार्च तक एडमिशन पूरे कर लिए थे। केजी-1 में एडमिशन होने से इन स्कूलों में पिछले सत्र का रोटेशन तो बन गया था। लेकिन इस बार नर्सरी में न के बराबर एडमिशन हुए हैं, तो पूरा सत्र खाली जाएगा और अगले सत्र में केजी-1 में बच्चे नहीं होंगे।

डर के मारे नहीं हो रहे एडमिशन

सीबीएसई स्कूलों ने जनवरी फरवरी में ऑफलाइन प्रवेश शुरू किए थे। फरवरी के बाद स्कूल बंद हो गए। ऐसे में ऑनलाइन पोर्टल से प्रवेश शुरू हुए, लेकिन उसमें किसी पैरेंट ने बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। इसके पीछे अनिश्चतता का माहौल बताया जा रहा है। पहला तो कोरोना को देखते हुए आगे स्कूल लगेंगे या नहीं। यह साफ नहीं है।

स्कूलों की स्थिति और भी खराब

एमपी बोर्ड के में अप्रैल में प्रवेश शुरू होते हैं, लेकिन मार्च से स्कूल बंद हो गए हैं। ऐसे में सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में अभी एडमिशन शून्य हैं। 22 मार्च 2020 से लॉकडाउन के बाद एमपी बोर्ड के स्कूलों में नर्सरी, केजी-1 या फर्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं हो पाए और पूरा साल जीरो हो गया था।

क्या कहते हैं स्कूल संचालक

हमने जनवरी से एडमिशन प्रक्रिया शुरू की थी और पिछले वर्ष कोरोना की मार के कारण हमने पैरेंट्स पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया था। इसी का परिणाम है कि प्रवेश प्रक्रिया धीमी चली और बमुश्किल 20 प्रतिशत एडमिशन हो सके हैं, जबकि हर बार लगभग 250 एडमिशन होते हैं, लेकिन अभी तक नर्सरी में सिर्फ 50 बच्चे ही आए हैं।

विनीराज मोदी, संचालक, ज्ञानगंगा इंटरनेशनल एकेडमी, भोपाल

कोरोना के कारण लोगों भविष्य सुरक्षित नहीं दिख रहा है। यही कारण है कि हमने ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू की है, लेकिन पैरेंट्स रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं। जनवरी-फरवरी में ऑफलाइन 50 एडमिशन हुए हैं। आमतौर लगभग 300 बच्चे नर्सरी में एडमिशन लेते थे। यदि यही स्थिति रही तो इन्हीं 15 फीसदी बच्चों के साथ सत्र शुरू करना होगा।

बाबू थॉमस, संचालक, सेंट जार्ज स्कूल ग्रुप

एमपी बोर्ड के स्कूलों में अप्रैल से प्रवेश शुरू होता है, लेकिन मार्च से कोरोना के कारण स्कूल बंद हो गए हैं। परिणामस्वरूप अभी तक किसी भी स्कूल में एक भी एडमिशन नहीं हुआ है। पिछले वर्ष भी मार्च से लॉकडाउन लगने के कारण नर्सरी में एडमिशन नहीं हुए थे, पूरा सत्र शून्य रहा है। अब इस बार नर्सरी में तो बच्चे होंगे नहीं और केजी-1 की क्लास भी खाली रहेंगी।

अजीत सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, प्रायवेट स्कूल एसोसिएशन, मप्र

वेतन मिलने में हो रही देरी, अध्यापक संगठन ने जताई नाराजगी

भोपाल। जिला शिक्षा केंद्र अंतर्गत पदस्थ एपीसी, बीआरसी, बीएसी, जन शिक्षक, संविदा कर्मी एवं अन्य कर्मचारियों को समय पर माह में वेतन भुगतान नही हो पा रहा है। ऐसे में शासकीय अध्यापक संगठन ने नाराजगी जाहिर करते हुए सीईओ जिला पचांयत की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। शासकीय अध्यापक संगठन के प्रदेश संयोजक उपेन्द्र कौशल का कहना है कि उक्त कर्मचारियों के वेतन भुगतान की फाइल पहले जिला पंचायत से अनुमोदन होने के पश्चात ही वेतन भुगतान की कार्यवाही होती है। सीईओ द्वारा अन्य फाइलों या अन्य कार्यो के लिए हर माह वेतन भुगतान की फाइल में अनावश्यक विलंब होता है। इससे डीपीसी के अंतर्गत पदस्थ कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है, जिससे आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं।

सर्व शिक्षा कर्मचारियों को नहीं हुआ अप्रैल का वेतन भुगतान

जिला पंचायत ने कहा वेतन भुगतान की प्रक्रिया चल रही है, बीआरसीसी ने समय पर नहीं भेजी संक्रमित शिक्षकों की जानकारी

भोपाल ■ राज न्यूज़ नेटवर्क

सर्व शिक्षा अभियान के अधीन डीपीसीसी लेकर बीआरसी कार्यालयों और संकुल केंद्रों पर काम कर रहे शैक्षणिक एवं अन्य स्टाफ को अप्रैल माह के वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। इधर जिला पंचायत में अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए प्रक्रिया चल रही है। कर्मचारियों का कहना है कि राजधानी भोपाल के जिला शिक्षा केंद्र अंतर्गत पदस्थ एपीसी, बीआरसी, बीएसी जन शिक्षक संविदा कर्मी एवं अन्य कर्मचारियों को सब पर माह में वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है। ज्ञात हो कि उक्त कर्मचारियों के वेतन भुगतान की फाइल पहले जिला पंचायत से अनुमोदन होने के पश्चात ही वेतन भुगतान की कार्यवाही होती है। अन्य फाइलों अथवा अन्य कार्यों को लेकर हर माह वेतन भुगतान की फाइल में अनावश्यक रूप से विलंब किया जा रहा है। जिसके कारण डीपीसी कार्यालय अंतर्गत पदस्थ उपरोक्त कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। समय पर वेतन नहीं मिल पाने से इन कर्मचारियों को अनेकों आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसी के बैंक किश्त होम लोन किश्त पारिवारिक समस्या बच्चों के फीस बीमारी का इलाज इत्यादि समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। कोरोना महामारी के दौरान जहां कर्मचारी पहले से ही आर्थिक रूप से पीड़ित है। वहीं समय पर वेतन ना मिल पाने से वह अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे करें। जन शिक्षक एवं अध्यापक नेता उमेंद्र कौशल का कहना है कि ऐसे समय पर हर माह कर्मचारियों को वेतन भुगतान कर इनकी आर्थिक समस्याओं का निराकरण कर उदारता दिखाई जाए। वेतन भुगतान की फाइल लटकाकर कर्मचारियों को आर्थिक रूप से परेशान होना पड़ रहा है। जबकि शासन के स्पष्ट आदेश है कि हर कर्मचारी को माह की पहली तारीख को वेतन भुगतान किया जाना सुनिश्चित हो।

वेतन भुगतान की प्रक्रिया चल रही है: विकास मिश्रा

इस संबंध में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विकास मिश्रा का कहना है कि सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत लोक सेवकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा है कि कुछ जन शिक्षकों एवं कर्मचारियों को कोरोना हो गया था। उन्होंने कहा है कि इसके कारण वेतन भुगतान में थोड़ा विलंब हुआ है। उन्होंने उन्होंने कहा है कि जल्द ही वेतन का भुगतान किया जाएगा। इधर जानकारी यह भी है कि कुछ जन शिक्षकों एवं कर्मचारियों को कोरोना हो गया था जो घरों में ही क्वॉरेंटाइन थे। इनकी प्रमाणित जानकारी समय से बीआरसीसी द्वारा डीपीसी कार्यालय को भेजी जानी थी। बीआरसीसी द्वारा समय पर यह जानकारी नहीं भेजने के कारण वेतन में विलंब हुआ है। इसके पीछे बीआरसीसी की लापरवाही भी मानी जा रही है। जबकि शासन के आदेश अनुसार डीपीसी और बीआरसीसी कार्यालय में 10 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य थी। उसके बाद भी इस कार्य में लापरवाही हुई है। जिसके कारण निर्दोष जन शिक्षकों बीएससी एपीसी एवं अन्य कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है।

स्थाई कर्मचारियों को पिछले दो महीने से नहीं दिया गया है वेतन

भोपाल। वन एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधीन स्थाई एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। आरोप है कि नौकरशाही के कारण वेतन में विलंब हुआ है। जिसके कारण परिवारों में आर्थिक तंगी का माहौल बन गया है। स्थाई कर्मी कल्याण संघ के प्रांत अध्यक्ष शारदा सिंह परिहार ने बताया कि मध्य प्रदेश के स्थाई कर्मियों को माह मार्च अप्रैल 2021 का वन मंडल सिवनी एवं उत्तर वन मंडल शहडोल का वेतन भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया है। आदिम जाति कल्याण विभाग सिवनी में भी विगत 3 माह से वेतन भुगतान नहीं किया गया। इस भीषण महामारी के दौर पर वेतन भुगतान न होना विकट समस्याओं को जन्म देता है। स्थाई कर्मी अपनी राशन सामग्री स्कूल फीस बिजली बिल जमा करने में असमर्थ है।

कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि नौकरशाही कर रही लापरवाही

मानसिक तथा आर्थिक रूप से प्रताड़ना का सामना कर रहा है। शीघ्र वेतन भुगतान कराए जाने के संबंध में विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से लगातार मांग की जा रही है। आरोप है कि नौकरशाह बेपरवाह बने हुए हैं। जिससे स्थाई कर्मियों का परिवार भूखों मरने की कगार पर आता जा रहा है। संगठन के महामंत्री गोविंद तिवारी ने बताया कि सामान्य परिस्थितियों में रोजमर्रा की चीजें दुकानों से उधार प्राप्त कर ली जाती थी। लेकिन इस महामारी के दौर में लॉकडाउन के चलते यह व्यवस्था भी सुलभ नहीं है। ऐसी स्थिति में आखिर रोजमर्रा की चीजें कैसे प्राप्त की जाए यह एक बड़ी समस्या स्थाई कर्मी के समक्ष आ गई है। अगर शीघ्र वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो फिर आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

स्कूल खुलेंगे या नहीं इस पर 15 मई के बाद होगा फैसला, पेरेंट्स बोले- न वैक्सीन, न व्यवस्थाएं... आखिर कैसे रहेंगे बच्चे सुरक्षित ?

अब कोविड-19 की तीसरी लहर की संभावना ने बढ़ाई चिंता, अभी स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं अभिभावक

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर स्कूली व्यवस्था को बेपटरी कर दिया है। परीक्षाओं के साथ-साथ इस बार ऑनलाइन कक्षाएं भी संक्रमण से प्रभावित हुई हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग ने दसवीं-बारहवीं की कक्षाओं को छोड़कर सभी कक्षाओं के लिए एक माह तक ऑनलाइन कक्षाएं बंद रखने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में फिलहाल बच्चे घरों में हैं और स्कूलों के खुलने को लेकर असमंजस बरकरार है। इसके साथ ही अब कोविड-19 की तीसरी लहर की संभावना ने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। अभिभावकों का कहना है कि फिलहाल 6 माह तक स्थिति सुधरती नजर नहीं आ रही है।

ऐसे में फिलहाल स्कूलों को खोलने कोई गुंजाइश नहीं है। मुख्य बात यह भी है कि स्कूली बच्चों के लिए न तो कोई वैक्सीन उपलब्ध है और न स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था, ऐसे में बच्चे सुरक्षित कैसे रहेंगे। हालांकि स्कूल शिक्षा मंत्री ने स्कूलों के खुलने को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि फिलहाल 15 मई तक कोरोना कर्फ्यू पूरे प्रदेश में लागू है। इसके बाद कोरोना संक्रमण की स्थिति और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को खोलने के संबंध में कोई निर्णय लिए जाएगा।

कोई गुंजाइश नहीं

कोरोना संक्रमण जिस हिसाब से तेजी से फैल रहा है और लगातार जिस तेजी से [illegible] रहा है। ऐसे में फिलहाल 6 माह तक तो स्थिति सुधरती नजर नहीं आ रही है। कई जगह से यह भी सुनने में आ रहा है कि कोविड-19 की तीसरी लहर भी आएगी। ऐसे में फिलहाल स्कूलों को खोलने कोई गुंजाइश नहीं है। एक मुख्य बात यह है कि स्कूली बच्चों के लिए न तो कोई वैक्सीन उपलब्ध है और न स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था हो पाएगी।

प्रबोध पंड्या, समाजसेवी, पालक महासंघ, मप्र

अभी सही समय नहीं

यह समय मेडिकल इमरजेंसी का है। स्कूलों को खोलना फिलहाल बिल्कुल सही नहीं होगा। शिक्षा व्यवसाय नहीं है, यह एक समाज सेवा कार्य है। स्कूलों को अब इस बात को समझना चाहिए कि इस दौर में वह भी लोगों की मदद के लिए आगे आए और एंबुलेंस, चिकित्सा जैसी सेवाएं भी बच्चों को उपलब्ध कराएं। क्योंकि भविष्य में कोविड-19 की तीसरी लहर की संभावना भी है।

अभिषेक शर्मा, पेरेंट्स

कोई समझौता नहीं होगा

वर्तमान स्थिति को देखते हुए स्कूल खोलना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि अभिभावक के लिए सबसे मुख्य बच्चों की सुरक्षा होती है। अगर स्कूल खोले भी जाए तो हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। हम बच्चों को एक साल घर बैठा सकते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। वैसे भी बीते डेढ़ साल से हम ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं।

शिल्पा शेट्टी, पेरेंट्स

परिस्थिति के अनुसार लिया जाएगा निर्णय

फिलहाल 15 मई तक कोरोना कर्फ्यू पूरे प्रदेश में लागू है। इसके बाद कोरोना संक्रमण की स्थिति और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही परिस्थिति अनुसार स्कूलों को खोलने के संबंध में कोई निर्णय लिया जाएगा।

इंदर सिंह परमार, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्कूल शिक्षा

वर्क फ्रॉम होम सुविधा ले सकेंगी

दिव्यांगों व गर्भवती महिला कर्मियों को ऑफिस आने की जरूरत नहीं

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ऑफिस अटेंडेस नियमों में कई बदलाव किए हैं। कई तरह के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी दी गई है।

केंद्र सरकार द्वारा गुरुवार को जारी एक संशोधित सर्कुलर में कहा गया है कि दिव्यांगों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को ऑफिस आने की जरूरत नहीं होगी और वे वर्क फ्रॉम होम सुविधा का लाभ उठा सकेंगी। गौरतलब है कि देश में कोरोना संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में पूर्ण ▶▶ शेष पेज 6 पर

अटेंडेंस रेगुलेट करने की जिम्मेदारी सचिवों की

संशोधित नियमों में कहा गया है कि दफ्तरों और अन्य जगहों पर कोविड पॉजिटिव मामलों को देखते हुए सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिवों की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने कर्मचारियों के अटेन्डेंस को रेगुलेट करें। केंद्र सरकार के सभी विभागों में ▶▶ शेष पेज 6 पर

कंटेनमेंट जोन के कर्मी फोन से संपर्क में रहें

ऑर्डर में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के अधिकारियों, कर्मचारियों को तब तक वर्क फ्रॉम होम की इजाजत है जब तक उनका यह जोन डीनोटिफाइड नहीं हो जाता यानी सामान्य घोषित नहीं हो जाता। 'कंटेनमेंट जोन में रहने वाले अधिकारी और कर्मचारी घर से काम कर सकते हैं और उन्हें हर समय फोन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से संपर्क में रहना होगा।

दैनिक भास्कर
भोपाल 08-05-2021

संभलिए... पर्यावरण बचाइए, नहीं तो स्कूल बैग की बजाय बच्चों के कंधे पर होंगे ऑक्सीजन के उपकरण

चलो बच्चों से सीखें : ऑक्सीजन का महत्व समझाने के लिए 4 वर्ष के दियांश दूधवाला ने अपनाया अनोखा तरीका

सूरत | कोरोना वायरस की मार और ऑक्सीजन संकट के बीच सूरत में चार साल के दियांश दूधवाला ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन कर पर्यावरण संरक्षण की अपील की। एक पारदर्शी कंटेनर में एक पौधा रख कर इसे नली-मास्क से जोड़कर सड़क पर मार्च कर संदेश दिया कि पौधा ऑक्सीजन का उत्सर्जन कर रहा है। नली-मास्क सहित डिवाइस के जरिए सांस ली जा रही है। जीत फाउंडेशन इंडिया नामक संस्था के सहयोग से दियांश दूधवाला इस उपकरण के साथ हीरानगरी में जगह-जगह मार्च कर जागरूकता बढ़ाने के लिए सक्रिय हैं। दियांश दूधवाला कहते हैं- 'पेड़-पौधे पृथ्वी पर बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हैं तो ऑक्सीजन है। अब भी यदि लोगों ने वृक्षों का ख्याल रखना शुरू नहीं किया तो वे दिन दूर नहीं, जब बच्चों को कंधे पर स्कूल बैग की बजाय ऑक्सीजन के लिए डिवाइस लेकर चलना पड़ेगा।'

करने का फैसला लिया है।

के मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ कपूर, यस बाई बैंक की चेयरमैन श्रीमती ... कपूर मौजूद थी।

खाद्य औषधि प्रशासन से लेकर पंचायत ग्रामीण उच्च शिक्षा में शत-प्रतिशत उपस्थिति

सरकारी कार्यालयों में लगातार कोरोना का कहर फिर भी मान नहीं रहे अफसर

भोपाल(आरएनएन)। एक तरफ सरकारी कार्यालयों में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर जवाबदार अधिकारी सरकार की गाइडलाइन मानने को तैयार नहीं है। कई विभाग ऐसे हैं जहां पर कर्मचारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की जा रही है। पिछले दिनों खाद्य एवं औषधि प्रशासन में कर्मचारियों द्वारा किए गए विरोध का असर भी अधिकारियों की सेहत पर नहीं हुआ है। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े इस विभाग में व्यवस्थाएं चौपट दिख रही है। सरकार के नियम के अनुसार यहां पर भी कंट्रोल रूम बनाया गया है। उसका दूरभाष नंबर सार्वजनिक होना चाहिए लेकिन इस गंभीर विषय में जवाबदार अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। कर्मचारी पीड़ित है कि एक तरफ यहां पर शत-प्रतिशत उपस्थिति बुलाई जा रही है। दूसरी ओर दूरभाष नंबर सार्वजनिक नहीं होने के कारण सीधे आम व्यक्ति कार्यालय में दस्तक दे रहा है। यही कारण है कि यहां संक्रमित मरीजों की संख्या 2 दर्जन हो चुकी है। संक्रमण के कारण 2 दिन पहले ही एक महिला कर्मचारी की मौत हो चुकी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में भी आदेश निकाल दिया गया है कि यहां कर्मचारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत रहेगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर से लेकर अन्य कर्मचारियों को यहां समय पर कार्यालय आने के लिए कहा गया है। विंध्याचल में संचालित विद्युत सुरक्षा में भी सभी कर्मचारियों को बुलाया जा रहा है। सतपुड़ा में लगने वाले उच्च शिक्षा विभाग की भी यही स्थिति है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को लिखा जाएगा पत्र: वरिष्ठ कर्मचारी नेता अनिल भटोरिया का कहना है कि इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा जाएगा। उन्होंने कहा है कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन में सबसे बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। यह विभाग स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा हुआ है। जहां पर शत-प्रतिशत उपस्थिति होने के बाद भी अधिकारी काम में लापरवाही कर रहे हैं। मुख्य कार्यालय में हुए अधिकारियों ने महामारी संक्रमण से लड़ने कंट्रोल रूम बनाया है। दुर्भाग्य देखिए कि इसका दूरभाष नंबर सार्वजनिक नहीं किया गया है। जबकि यह कार्य करना अति आवश्यक था। अधिकारी अपनी जवाबदारी से बच सकें। इस कारण यह नंबर सार्वजनिक नहीं किया गया है। जिसका नतीजा है कि औषधि लाइसेंस अन्य सूचना की जानकारी करने के लिए सीधे आम व्यक्ति कार्यालय में आ रहा है। यही कारण है कि यहां पर तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है।

लापरवाह अधिकारियों पर होना चाहिए कार्यवाही: वरिष्ठ कर्मचारी नेता विजेंद्र सिंह का कहना है कि शासन की गाइड लाइन का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर तत्काल कार्यवाही होना चाहिए। जब संक्रमण तेज रफ्तार से फैल रहा है तो अधिक कार्यालय में भीड़ जोड़ने का क्या औचित्य है। ऐसा नियंत्रण रखा जाए कि कर्मचारी घर से ही काम कर सकें। अगर अति आवश्यक हो तभी कार्यालय में बुलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि नौकरी का विस्तार करने में अधिकारियों की भी कहीं ना कहीं लापरवाही है। इस कारण ऐसे अधिकारियों पर कार्यवाही होना चाहिए।

दिल्ली हाईकोर्ट

10वीं, 12वीं के परीक्षार्थियों को लगवाई जाए कोविड वैक्सीन

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केन्द्र और दिल्ली सरकार को कक्षा दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को कोरोना वैक्सीन लगाने के बारे में जानकारी देने को कहा। न्यायालय वर्ष 2020-21 सत्र की दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को कोरोना वैक्सीन लगाने से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने वकील ज्योति अग्रवाल, संजीवनी अग्रवाल और प्रदीप शेखावत की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय तथा दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करके इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा।

शिक्षक बोले- पहले हमें कोरोना योद्धा घोषित करो, तब ड्यूटी पर तैनात करो

अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन देते शिक्षक।

आरोपः न ट्रेनिंग न सुरक्षा उपकरण और घर-घर सर्वे में लगा दी ड्यूटी

भास्कर संवाददाता | शिवपुरी

न तो शिक्षकों को सर्वे कार्य की ट्रेनिंग दी गई और न ही मेडिकल उपकरण दिए गए। यही नहीं घर- घर जाने के लिए मास्क, सेनाटाइजर और पीपीई किट तक नहीं दी गई। ऐसे में शिक्षकों को सीधा आदेश जारी कर उनसे सर्वे कराया जा रहा है। जबकि सरकार ने उन्हें कोरोना योद्धा तक घोषित नहीं किया है। यदि किसी शिक्षक के साथ कोई अनहोनी हो गई तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। उसका परिवार तो सड़कों पर आ जाएगा।

दरअसल किल कोरोना अभियान के तहत तकरीबन 300 शिक्षकों की ड्यूटी सर्वे कार्य में लगा दी है। शिक्षकों का आरोप है कि कोई सर्वे कराया जाता है तो पहले उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन मेडिकल हिस्ट्री जानने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। और तो और ना गन मशीन दी गई और ना ही सुरक्षा उपकरण। ऐसे में घर-घर जाने का काम शिक्षकों को सौंप दिया है। और वह इस काम को करने मजबूर भी है, क्योंकि जो शिक्षक सर्वे पर नहीं जाएगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन प्रशासन द्वारा लिया जाएगा ।ऐसे में शिक्षकों के सामने समस्या यह है कि वह कैसे बिना सुरक्षा उपकरणों के ड्यूटी करें। -ना मास्क, ना सैनिटाइजर, और ना ही पी पी ई किट, कब तक सुरक्षित रहेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र जैन, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के सुशील अग्रवाल,अजमेर सिंह यादव सहित अन्य शिक्षकों ने एसडीएम से मांग की है कि वह शिक्षकों को इस कार्य से अव्वल तो मुक्त करें।नहीं तो उन्हें मास्क, सेनाटाइजर और पीपीई किट प्रदान करें ताकि वह सुरक्षा के साथ अपनी ड्यूटी कर सके। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति जब घर से बाहर निकलता है तो वह लोगों से संपर्क करने के दौरान सुरक्षा के पूरे उपकरण साफ रखता है। ऐसे में अभी हम पर यह उपकरण नहीं कोई शिक्षक कोरोना की चपेट में आया और यदि उसकी मौत हो गई तो फिर उसका परिवार बिखर कर सड़कों पर आ जाएगा।

कोरोना योद्धा घोषित करें सरकार शिक्षक नेताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि जिस तरह से उज्जैन में कोरोना ड्यूटी कर रहे शिक्षकों को कोरोना फाइटर बनाया है। वही प्रक्रिया शिवपुरी में घोषित हो ताकि उनके साथ कभी कोई अनहोनी घटित होती है तो कम से कम परिवार को इतना मुआवजा तो मिल जाए कि उसे भूखों मरने की नौबत न आए।

पेंच यहां फंस रहा- प्रशासन कोरोना में ड्यूटी दिखाते हुए अनुशंसा करे, तभी मिलेगा कोरोना योद्धा का सम्मान... लेकिन ऐसा हो नहीं रहा

शिक्षकों को कोरोना योद्धा माना,लेकिन मौत पर नहीं दिए 50 लाख

इंदौर | DBStar

शिक्षा विभाग ने कोरोना ड्यूटी में लगे शिक्षकों को 'योद्धा' तो माना है, लेकिन आज तक किसी भी मृत शिक्षक के आश्रितों को न तो 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी और न इलाज का खर्च। और तो और, डिजिटल मृत्यु प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के कारण 50 हजार रुपए की तात्कालिक सहायता राशि भी परिजन को नहीं मिल सकी है, जबकि सरकार ने खुद माना है कि कोरोना से सालभर में 441 शिक्षकों की मौत हो गई है। शिक्षा विभाग के अधिकारी का कहना है कि सरकार ने शिक्षकों को भी कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया है। सरकार की नीति के तहत कोरोना व्यवस्था में ड्यटी करने वाले शिक्षकों का इलाज शासन के खर्च पर होगा। मौत होने पर कोरोना योद्धा के लिए निर्धारित राशि (50 लाख रुपए) मृतक के परिजन को मिलेगी। विभाग के अनुसार सालभर में 675 शिक्षकों की मौत हुई है, जिनमें 441 की मौत कोरोना से और 234 का निधन अन्य बीमारियों या दुर्घटनाओं में हुआ है। इसके बावजूद किसी भी शिक्षक के परिजन को सरकार ने 50 लाख रुपए नहीं दिए। सालभर से शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव, मोहल्ला कक्षा, कोरोना सर्वे, टीकाकरण और टोल नाकों से लेकर श्मशान तक में लगाई जा रही है। शिक्षकों की ड्यूटी के अधिकांश आदेश वाट्स एप या सादे कागज पर चार्ट बनाकर जारी किए। यानी,

50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि भी नहीं मिल रही परिजनों को मौत पर

441 शिक्षकों की मौत हो चुकी है कोरोना से, यह सरकार ने भी माना

प्रशासन की तरफ से शिक्षकों को बहुत कम आदेश विधिवत या व्यक्तिगत मिले हैं। इसके अलावा शिक्षकों के बीमार होने पर प्रशासन द्वारा उन्हें अच्छे अस्पतालों में भर्ती करवाना तो दूर, इलाज की राशि भी स्वीकृत नहीं की है। शिक्षकों के परिजनों को कोरोना योद्धा का सम्मान भी तभी मिल सकता है, जब प्रशासन उनकी ड्यूटी कोरोना व्यवस्था में दिखाते हुए अनुशंसा करे। प्रशासन की इस लापरवाही का खामियाजा शिक्षकों और उनके परिजन को भुगतना पड़ रहा है। आश्चर्य तो यह है कि जिन शिक्षकों की विधिवत ड्यूटी कोरोना व्यवस्था में लगाई गई थी, उनकी मौत पर भी प्रदेशभर के जिला अधिकारी खामोश हैं।

ऑनलाइन प्रक्रिया बनी अनुग्रह राशि में रोड़ा

स्कूल शिक्षा और जनजातीय विभाग इन दिनों यह गिनती करने में व्यस्त हैं कि किस जिले में कितने शिक्षकों की कोरोना से मौत हुई, लेकिन उनके परिवार को क्या और कैसे राहत दी जाए इस बारे में विभाग के पास योजना नहीं है। समग्र शिक्षक संघ का आरोप है कि कोरोना से दिवंगत शिक्षकों की संख्या भले ही सरकारी आंकड़ों में 441 बताई जा रही है, लेकिन वास्तविकता में आंकड़ा इससे ज्यादा है। प्रदेश में डिजिटल मृत्यु प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के कारण दिवंगत शिक्षकों के आश्रित परिजनों को 50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान भी अटक गया है। नगर निगम के जोन कार्यालयों में ऑनलाइन प्रक्रिया में प्रमाण पत्र बनने में समस्या आ रही है। शिक्षकों की मांग है कि भुगतान प्रक्रिया ऑफ्लाइन की जाए।

28 शिक्षक और दो भृत्य को लील चुका है कोरोना

एडीपीसी नरेंद्र जैन के अनुसार इंदौर जिले में 6 अप्रैल 2021 तक 397 शिक्षक कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इनमें से 28 की मौत हुई जिनमें दो प्रिंसिपल भी शामिल हैं। इनके अलावा दो चपरासी की भी मौत हुई है। शिक्षक संगठनों के अनुसार उज्जैन, देवास सहित करीब 10 जिलों में कलेक्टरों ने शिक्षकों को कोरोना योद्धा घोषित किया है।

सीधी बात

प्रमोद कुमार सिंह, उप सचिव, स्कूल शिक्षा

कलेक्टर की जिम्मेदारी है कोरोना में लगे शिक्षकों को सम्मान राशि दिलवाना

प्रदेश में शिक्षकों की ड्यूटी कोरोना व्यवस्था में लगाई जा रही है। अब तक कितने शिक्षकों का कोरोना से निधन हो चुका है?

- शिक्षकों की कोरोना ड्यूटी जिला प्रशासन लगा रहा है। प्रदेश में कोरोना से 441 शिक्षकों का निधन हुआ है।

महामारी में ड्यूटी करने के बाद भी शिक्षकों को कोरोना योद्धा क्यों नहीं माना जा रहा है?

- ऐसे शिक्षकों को भी सरकार ने कोरोना योद्धा का दर्जा दे रखा है।

लेकिन किसी भी मृत शिक्षक के परिजन को को 50 लाख की सम्मान निधि नहीं मिली है?

यह काम कलेक्टर का है। वे ही इनकी ड्यूटी लगाते हैं। कलेक्टर अनुशंसा करेंगे तो शासन जरूर राशि देगा। इसी तरह इलाज का प्रबंध भी प्रशासन को ही करना है।

शिक्षकों के परिजन क्लेम करें, इसके बाद सरकार को भेजेंगे अनुशंसा

शिक्षकों को शासन ने पहले ही कोरोना योद्धा माना है। इसलिए जिला प्रशासन अलग से इसकी घोषणा नहीं करेगा। कोरोना में ड्यूटी करते हुए संक्रमित होने पर जिन शिक्षकों की मृत्यु हुई है, उनके परिजन स्थानीय तहसीलदार या एसडीएम के माध्यम से क्लेम करें। प्रशासन सरकार को इसकी अनुशंसा कर देगा। **अभय बेड़ेकर,** अपर कलेक्टर और कोरोना ड्यूटी प्रभारी

एक माह में 45 शिक्षकों की मौत, उन्हें भी कोरोना योद्धा का दर्जा दे शासन

राज्य शिक्षक संघ ने की अनुकंपा नियुक्ति की मांग

पीपुल्स संवाददाता ● खरगोन

मो.नं. 9425090106

कोविड के प्रकोप से जिले में दिन-प्रतिदिन हो रही शिक्षकों की मृत्यु से शिक्षक संवर्ग में चिंता है। जिले में विगत एक माह में 45 शिक्षक साथियों की मृत्यु हो चुकी है... ऐसे में शिक्षकों एवं उनके परिवार की चिंता को लेकर राज्य शिक्षक संघ ने शासन से मृत शिक्षकों को कोरोना योद्धा का दर्जा देने की मांग की है। राज्य शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष प्रभुराम मालवीया ने बताया कि कोरोना काल में संपूर्ण मध्यप्रदेश में सैकड़ों शिक्षक काल के गाल में समा गए हैं। जिले के 7 आदिवासी जनपद क्षेत्रों में 37 एवं शिक्षा विभाग के बड़वाह एवं कसरावद ब्लॉक में 8 शिक्षक काल के गाल में समा गए। एक माह में इतने अधिक हुई शिक्षकों की मृत्यु से शिक्षक वर्ग चिंतित एवं भयभीत हैं। शिक्षकों के परिजन अपने भविष्य को लेकर चिंतित और परेशान हैं। कठिन नियमों के चलते हैं अनुकंपा नियुक्ति में आने वाली दिक्कतों से पहले ही परेशान हैं, वहीं पुरानी पेंशन बंद होने से परिवार आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। राज्य शिक्षक संघ ने मृत शिक्षकों को कोरोना योद्धा का दर्जा देकर उनके परिजन को 50 लाख राशि देने की मांग की है।

शिक्षकों को कब मिलेगी 7वें वेतनमान की तीसरी किश्त

कर्मचारी संघ ने विकासखंड के अफसरों पर लगाया आरोप

पीपुल्स संवाददाता ● जबलपुर

editor@peoplessamachar.co.in

शिक्षको को 7वें वेतनमान की तीसरी किश्त गत वर्ष मई माह में राज्य शासन ने रोक दी थी। वहीं फरवरी 2021 में शिक्षकों को एरियर्स का भुगतान करने निर्देश दिए थे। इसके विपरीत विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी शहपुरा एवं पनागर की तनाशाही के चतले उक्त विकास खण्ड के शिक्षकों को आज तक एरियर्स राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

इस संबंध में मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने बताया कि शासन द्वारा माह फरवरी 2021 में एरियर्स भुगतान पर लगी रोक हटाते हुए शिक्षकों एवं कर्मचारियों को माह मार्च 2021 तक 7वें वेतनमान के एरियर्स की तृतीय किश्त भुगतान करने के निर्देश दिए गए थे, किन्तु एरियर्स राशि का कुछ भाग कर्मचारी के जीपीएफ खाते में भी जमा किया जाना है। समय पर एरियर्स राशि आहरित न होने से ब्याज का नुकसान होगा, जिससे उक्त विकास खण्ड के शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है।

संघ के अटल उपाध्याय, नरेन्द्र दुबे, मुन्नालाल पटैल, मुकेश सिंह, आलोक अग्निहोत्री, दुर्गेश पाण्डे, दिनेश मिश्रा, दिनेश सिंह ठाकुर, कमलेश जैन, होरीलाल चडार, अच्छेलाल झारिया, मदन तिवारी, विष्णु दिघरा, तरूण पंचोली, नितिन अग्रवाल, मनीष लोहिया, मो० तारिख, धीरेन्द्र सोनी, प्रियांशु शुक्ला, संतोष तिवारी, महेश कोरी, श्यामनारायण तिवारी, आदि ने कलेक्टर से विकास खण्ड शहपुरा एवं पनागर के शिक्षकों को 7वें वेतनमान के एरियर्स के शीघ्र भुगतान की मांग की है।

शिक्षक योग कराकर दे रहे निरोग रहने का संदेश

कोठरी। योग आसन करते शिक्षक।

हरिभूमि न्यूज ▶▶| कोठरी

कोरोना संक्रमण के दौरान अस्वस्थ लोगों के नियमित योगा करने से लाभ मिल रहा है। नियमित योग करने से कई लाभ भी हो रहे हैं। शासन के निर्देशानुसार संकुल केंद्र कोठरी द्वारा बच्चों एवं पलोंको को योग कराया जा रहा है।

उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि योग प्राणायाम आसन करने से शरीर को बहुत लाभ मिलता है। इससे बीमारियां भी दूर हो जाती है। सभी रोगों का इलाज योग प्राणायाम से काफी हद तक हो जाता है। जो व्यक्ति नियमित योग करता है वह सदेव निरोगी बनकर रहता है।

शिक्षकों द्वारा बताया गया कि योग करने से क्या क्या गया लाभ मिलता हैं। नियमित प्राणायाम, योगिक क्रिया, व्यायाम, सूर्य नमस्कार के बारे में बताया जा रहा है। इस अवसर पर लखन वर्मा, मनोहर जैन, चन्दर तोमर, राजाराम कन्नोदिया, गजराज ठाकुर, ज्ञानसिंह मेवाड़ा आदि शिक्षक उपस्थित रहे। लोगों को संक्रमण से बचाव की जानकारी दी जा रही हैं।

शिक्षक पैंटिंग से सिखा रहे कोरोना से बचने का तरीका

हरिभूमि न्यूज ⏭ नसरुल्लागंज

तहसील के एक जागरुक शिक्षक ने लोगों को कोरोना के प्रति जागरुक करने व इससे लड़ाई के लिए तैयार करने का बीड़ा उठाया है। शिक्षक द्वारा अलग-अलग तरह की पैंटिंग बनाकर उसके माध्यम से लोगों को कोरोना के प्रति जागरुक करने का कार्य किया जा रहा है। शिक्षक संतोष धनवारे द्वारा ह्यूमैनिटी की इम्यूनिओ को मजबूत बनाना पड़ेगा, बहुत हो गया अब मौसम बदलना पड़ेगा स्लोगन के साथ तस्वीर बनाकर लोगों को इम्यूनिटी, ह्यूमैनिटी सहित कई अन्य जरूरी बातों को विस्तार से समझाया जा रहा है। शिक्षक संतोष धनावरे ने बताया कि आज शिक्षक को युग मे बदलाव के लिए आज की आवश्यकता के आधार पर खुद को ओर मजबूती से बदलने की पढने,समझने की ओर दुनिया को जानने की आवश्यकता आन पड़ी है।

हर शिक्षक को आगे आना होगा,एक राजनेता बनना होगा,तभी प्रलय से सृजन की ओर बदलाव होगा,आज पूरी मानवता का नैतिक दायित्व बन गया है कि दुनिया मे सकारात्मक विचार का प्रसारण होगा और नकारात्मकता क किया जा सकेगा।

संक्रमण कम होते ही निष्कासित अतिथि विद्वानों की होगी बहाली

उच्च शिक्षा विभाग ने कहा है कि कोरोना के कारण हो रहा है प्रक्रिया में विलंब

भोपाल ■ राज्य न्यूज नेटवर्क

प्रदेश में निष्कासित अतिथि विद्वानों की सेवा बहाली के प्रति उच्च शिक्षा विभाग चिंतित दिख रहा है। विभाग का कहना है कि कोरोना का संक्रमण जैसे ही कम होगा तत्काल निष्कासित अतिथि विद्वानों को सेवा में लिया जाएगा। इधर अतिथि विद्वानों का कहना है कि वह विगत 14 माह से बेरोजगारी के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। कोरोना काल के संकट में उनके परिवार का भरण पोषण करना उनके लिए विषम परिस्थिति बनी हुई है। अतिथि विद्वान के नेता डॉ बीएल दोहरे का कहना है कि सेवा से निष्कासित फालेन आउट अतिथि विद्वानों को जल्दी व्यवस्था मे लिया जाये। अतिथि विद्वान परिवार यही उम्मीद रखता है। कांग्रेस सरकार द्वारा 3148 सहायक प्राध्यापक ग्रंथपाल क्रीड़ा अधिकारी की पूर्व सरकार द्वारा दिसंबर 2019 में नियुक्ति देने से हमारे लगभग 2700 अतिथि विद्वान सेवा से बाहर हुए थे। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समय.समय पर सेवा से निष्कासित किए गए अतिथि विद्वानों को व्यवस्था में वापस लेने के लिए पोर्टल चालू किया गया न्यू ज्वॉइस फिलिंग के माध्यम से हमारे कई साथी व्यवस्था में वापस आ गए हैं। अभी भी हमारे लगभग 500-600 के आसपास अतिथि विद्वान और नौकरी से बाहर हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा फरवरी माह में 450 नए पदों की स्वीकृति के लिए फाइल वित्त विभाग में भेजी गई थी।

वित्त मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री दोनों का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त होने के बाद भी फाइल अभी भी पृष्ठांकन के लिए वित्त विभाग में वित्त प्रमुख सचिव के पास रखी हुई है। उन्होंने कहा है कि पिछले साल मौजूदा मुख्यमंत्री स्वयं हमारे आंदोलन में आए हुए थे। उस समय आपके द्वारा ही यह बोला गया था कि टाइगर अभी जिंदा है। मेरी उच्च शिक्षित बहनों को मुंडन कराने एवं दुपट्टा जलाने की नौबत आ गई है। यह मुझसे देखा नहीं गया। अतिथि विद्वानों को रिक्त पदों पर नियमित करना ही पड़ेगा। यदि सरकार नहीं करती है तो वह ईंट से ईंट बजा देंगे। हालांकि इस समय अतिथि विद्वान गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। क्योंकि उन्हें इस समय लगभग घर बैठे 14 महीने से ज्यादा हो गए हैं। कोरोना जैसी महामारी में वह अपने घर परिवार का भरण पोषण जैसी समस्याओं से गुजर रहे है। इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का कहना है कि निष्कासित अतिथियों को सेवा में लेने के लिए सरकार पूरी तरह गंभीर है। इस कारण वित्त विभाग को भी प्रस्ताव भेजा गया था लेकिन अभी सरकार के समक्ष महामारी संक्रमण को दूर करने की चुनौती है। जैसे ही यह संकट कम होगा तो अतिथियों की तत्काल सेवा बहाली होगी।

गरीब व्यक्तियों को समय पर खाद्यान्न वितरित करने के कलेक्टर ने दिए निर्देश

भोपाल। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अविनाश लवानिया ने सभी एसडीएम और जिला खाद्य अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि भोपाल जिले में कोविड-19 की रोकथाम के बचाव और गरीबों को तीन माह का एकमुश्त राशन वितरण किया जाए। उन्होंने कहा कि जिला खाद्य अधिकारी गरीबों को समय पर खाद्यान्न वितरण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने खाद्यान्न वितरण प्रणाली में सभी अधिकारी पारदर्शिता लाएं। मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिले के सभी गरीबों को अप्रैल, मई व जून का राशन निःशुल्क देने का निर्णय लिया है। माह अप्रैल का राशन वितरण हो चुका है। मई एवं जून का राशन दिया जाना है। कलेक्टर ने सर्वप्रथम जिला खाद्य अधिकारी से दुकानों के खुलने के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि कुछ दुकानें खुल चुकी है, कुछ खुलना शेष है। जिस पर कलेक्टर द्वारा गहन असंतोष प्रकट करते हुए खाद्य अधिकारी, सहायक खाद्य अधिकारियों, एसडीएम व सीईओ जनपद को निर्देश दिए हैं कि फील्ड में जाकर सभी उचित मूल्य दुकानें खुलवाएं और खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि इस कार्य को प्राथमिकता दें। और यह सुनिश्चित करें कि 15 मई के पूर्व सभी को खाद्यान्न मिल जाये।

में त्योहार के लिए खर्च होने वाली जरूरतमंदों की मदद के लिए खर्च करें

हिन्दी विश्वविद्यालय में ऑनलाइन योग शिविर का आयोजन

भोपाल(आरएनएन)। योग हमारी प्राचीन विधा है, जिससे हम समग्र स्वास्थ्य की अवधारणा करते हैं। योगासन हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं संबंधित अंगों को दृढ़ता प्रदान करता है। योग का मनःसंचारण आरंभ होता है। योग का लाभ शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से प्राप्त होता है। योग हमें लोक-परलोक, आध्यात्म की मूल दृष्टि प्रदान करता है, जिसके माध्यम से हम स्वयं से जुड़ सकते हैं। ये विचार यौगिक अध्यात्म विज्ञान विषय पर ऑनलाइन योग शिविर में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. रामदेव भारद्वाज ने व्यक्त किए। इस निशुल्क ऑनलाइन योग शिविर में आज 70 लोगों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में आभार व्यक्त करते हुए विश्वविद्यालय के कुलसचिव यशवंत सिंह पटेल ने कहा कि योग निरोग रहने की कुंजी है एवं योग के नियमित अभ्यास से हम समस्त व्याधियों से बचे रह सकते हैं।

इस दौरान आचार्य डॉ निलिम्प त्रिपाठी कहा कि योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसमें शरीर मन और आत्मा को समवेत किया जाता है। आज के समय में हम व्यथित हैं, दुःखी है, विचलित हैं। ऐसे समय में योग हमारी राह प्रशस्त करता है। इसमें जीवन का सार छुपा है। आचार्य त्रिपाठी ने आगे कहा कि मंत्र मणि और औषधि में भगवान का वास है। जीवन में भगवत भक्ति करते हुए उत्साह एवं आनंद में रहना चाहिए।

यू डाइस और उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लिए शिक्षकों को बुलाया बीआरसी ऑफिस

शिक्षक बोले: कोरोना का संकट तिथि आगे बढ़े

हरिभूमि न्यूज >> | गुना

कोरोना काल में एक ओर जहां कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या सीमित कर दी है, वहां शिक्षकों से यू डाइस एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र मांगे गए हैं। इतना ही नहीं, शिक्षकों को बीआरसी ऑफिस बुलाया गया है। जब शिक्षकों को ऑफिस बुलाया तो दूसरे शिक्षकों ने इस पर आपत्ति जताई। शिक्षकों ने कहा कि इन प्रमाण पत्रों को बीआरसी, सीएसी के माध्यम से स्कूलों से एकत्रित कर सकते हैं, लेकिन गुना में ऑफिस बुलाया जा रहा है। कोरोना काल में शिक्षकों की भीड़ लगने से संक्रमण का खतरा है।

दरअसल, शिक्षकों को इसलिए चिंता सता रही है। क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर में उपचार रत हैं एक विकास खंड अधिकारी, जन शिक्षक और बहुत से शिक्षक भी संक्रमित होकर विभिन्न स्थानों पर इलाज करवा रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी विभाग द्वारा यू डाइस फार्म विद्यालय के संस्था प्रधान को जिले के सभी बीआरसी कार्यालय में बुला कर फार्म दिए एवं भरवा कर वापस लिए जा रहे हैं। इस कारण शिक्षकों में संक्रमण बढ़ने का खतरा अधिक है। साथ ही स्कूल द्वारा 31 मार्च तक की व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ स्कूल की बैंक पासबुक एवं स्कूल की कैशबुक की फोटो कॉपी प्रत्येक स्कूल से

मांगी जा रही है जबकि गुना जिले में 17 मई तक लॉक डाउन होने के कारण फोटोकॉपी दुकानें बंद हैं। उधर, विभाग ने इन प्रमाण पत्रों को एकत्रित करने का समय 30 मई तक दे दिया है। इस वजह से शिक्षकों ने तिथि बढ़ाने की मांग उठाई है।

हो गया है गुना में निधन

गुना जिले में एक प्राचार्य सहित लगभग 15 शिक्षकों का कोरोना के कारण निधन हो चुका है। ऐसे समय में शिक्षकों से जानकारी मंगवाई जाना उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो सकता है। इसे लेकर राज्य कर्मचारी संघ ने आपत्ति जताई है। साथ ही संघ के सुरेंद्र सिंह चौहान, केजी मीणा, रामकृष्ण शर्मा, कमलेश श्रीवास्तव, अनिल परमार, सुरेंद्र प्रजापति, राजेश शर्मा, संतोष सक्सेना, रामेश्वर गहलोत, अनिल शर्मा, जितेंद्र ब्रह्मभट्ट, शरद श्रीवास्तव ने विभाग द्वारा मांगी गई जानकारी की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने की मांग की है।

तिथि बढ़ा दी जाए

[illegible]

[illegible] सिंह सोलंकी, बीआरसी गुना

सहायक ग्रेड-3, गंथपाल और प्रयोगशाला परिचायक की मौत हुई

गवर्मेंट कॉलेजों में प्राचार्य सहित 100 प्राध्यापक संक्रमित, 5 की मौत

शहर के कॉलेजों में 50 से अधिक प्राध्यापक कोरोना पीड़ित हैं

आशीष शर्मा ● ग्वालियर
मो.नं. 9098682242

कोरोना के कारण कॉलेज बंद हैं। छात्र-छात्राएं ऑनलाइन के जरिए पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रोफेसरों को कॉलेज जाना पड़ रहा है। उच्च शिक्षा विभाग ने 10 फीसदी स्टाफ को जाने की अनुमति दी है मगर इसके बाद भी प्रोफेसर व अन्य लोग संक्रमित हो रहे हैं। अंचल के गवर्मेंट कॉलेजों की बात करें तो 116 (प्राध्यापक, लैब टेक्नीशियन, ग्रंथपाल) कोरोना संक्रमित हो गए हैं, इनमें प्राध्यापकों की संख्या अधिक है। शहर की बात करें तो एसएलपी कॉलेज के प्राचार्य प्रो. आरएम अग्रवाल की कोरोना से मौत हो गई है, जबकि एमएलबी कॉलेज के प्राचार्य प्रो. केएस राठौर व वीरांगना झलकारी बाई कॉलेज के प्राचार्य प्रो. बीएल अहिरवार भी संक्रमित हैं और घर पर आइसोलेट हैं। साथी प्राध्यापकों के संक्रमित हो जाने पर दूसरे प्राध्यापक कॉलेज जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। शहर के कॉलेजों के 50 से अधिक प्राध्यापकों को कोरोना ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है।

इनकी हो चुकी है मौत

ग्वालियर: 4 प्राध्यापक की मौत, 55 प्राध्यापक संक्रमित, क्रीड़ाधिकारी, 1 ग्रंथपाल, 2 लैब टेक्नीशियन, 2 कर्मचारी संक्रमित।

गुना: ग्रंथपाल के के सक्सैना की मौत हो चुकी है। 8 प्राध्यापक संक्रमित हैं।

शिवपुरी: प्रयोगशाला परिचायक इंद्रराज धानुक व सहायक ग्रेड-3 पुरुषोत्तम दवे की मौत, 3 प्राध्यापक, 1 क्रीड़ाधिकारी, 1 प्रयोगशाला तकनीशियन, सहायक ग्रेड 2 व 3 के 1-1 कर्मचारी

श्योपुर: 8 प्राध्यापक संक्रमित हैं।

मुरैना: 9 प्राध्यापक और 1 ग्रंथपाल संक्रमित हैं।

भिंड: 5 प्राध्यापक संक्रमित हैं।

अशोकनगर: 8 प्राध्यापक संक्रमित।

दतिया: 6 प्राध्यापक संक्रमित हैं।

इनका कहना है

मैं 16 अप्रैल को कॉलेज से लौटा तो बदन में दर्द हुआ तो मैंने कोरोना टेस्ट कराया तो पॉजीटिव निकला साथ ही फेफड़ों में भी इन्फेक्शन था। मैं घर पर इलाज करा हूं और अब आराम हैं।

डॉ. केएस राठौर, प्राचार्य एमएलबी कॉलेज

शासन के आदेश पर 10 फीसदी स्टाफ ही कॉलेजों में आ रहा है, जो कि एहतियात बरत रहे हैं। बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। प्राध्यापक, ग्रंथपाल, लैब टेक्नीशिन संक्रमित हैं और इलाज करा रहे हैं।

डॉ. एमआर कौशल, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग

शहर के कॉलेजों में ये प्राध्यापक संक्रमित

साइंस कॉलेज: डॉ. आरके खरे प्राध्यापक वनस्पतिशास्त्र, डॉ. गरिमा शर्मा प्राध्यापक वनस्पतिशास्त्र, डॉ. डीबीआर श्रीवास्तव प्राध्यापक गणित, डॉ. एके त्रिपाठी प्राध्यापक गणित, डॉ. एचएस जाटव प्राध्यापक गणित, डॉ. सरिता श्रीवास्तव प्राणीशास्त्र, डॉ. अनीश पांडे प्राध्यापक रसायनशास्त्र, डॉ. एस मालती प्राध्यापक रसायनशास्त्र,

केआरजी कॉलेज: डॉ. आभा मिश्रा प्राध्यापक हिंदी, डॉ. पूर्णिमा शाह प्राध्यापक हिंदी, डॉ. अखिलेश गुप्ता प्राध्यापक समाजशास्त्र, डॉ. वीना लॉड प्राध्यापक अंग्रेजी, डॉ. संजय स्वर्णकार प्राध्यापक इतिहास, डॉ. विपिन कुमार बंसल प्राध्यापक वाणिज्य, डॉ. हरीश अग्रवाल प्राध्यापक वाणिज्य, डॉ. आनंद कुमार सिंह प्राध्यापक रसायनशास्त्र, डॉ. चारू चित्रा प्राध्यापक अंग्रेजी, डॉ. निशा मिश्रा प्राध्यापक अर्थशास्त्र, डॉ. आरबी रैपुरिया प्राध्यापक रसायनशास्त्र, डॉ. मोहित आर्य प्राध्यापक प्राणीशास्त्र।

झलकारीबाई कॉलेज: डॉ. बीआर अहिरवार प्राचार्य, डॉ. शुभा श्रीवास्तव प्राध्यापक राजनीतिशास्त्र, डॉ. भगवती आचार्य प्राध्यापक अर्थशास्त्र, डॉ. एके झा प्राध्यापक भूगोल, डॉ. विमलकांत श्रीवास्तव प्राध्यापक रसायनशास्त्र, डॉ. अनामिका कुजूर प्राध्यापक मनोविज्ञान।

भगवतसहाय कॉलेज: डॉ. सुनीता सोमानी प्राध्यापक अर्थशास्त्र, डॉ. सीता अग्रवाल प्राध्यापक अंग्रेजी, डॉ. शुक्ला प्राध्यापक इतिहास, डॉ. एके एके चंसौलिया प्राध्यापक हिंदी, डॉ. एनआर माहौर प्राध्यापक अर्थशास्त्र, डॉ. एमके उपाध्याय प्राध्यापक भौतिकी।

एसएलपी कॉलेज: डॉ. संजीव गुप्ता प्राध्यापक वाणिज्य, डॉ. डीके वाजपेयी प्राध्यापक राजनीतिशास्त्र, डॉ. देवेंद्र सिंह गुर्जर प्राध्यापक अर्थशास्त्र, डॉ. डीके मिश्रा प्राध्यापक गणित, डॉ. सुनीता वार्ष्णेय प्राध्यापक गणित, डॉ. जयेश कुमार मिश्रा, डॉ. साधना श्रीवास्तव।

एमएलबी कॉलेज: डॉ. केएस राठौर प्राचार्य, डॉ. कुसुम भदौरिया प्राध्यापक राजनीतिशास्त्र, डॉ. साधना अग्रवाल प्राध्यापक अंग्रेजी, डॉ. भारती कार्णिक प्राध्यापक अंग्रेजी, डॉ. वर्षा धाकड़ प्राध्यापक मनोविज्ञान, डॉ. रजी फराज खान प्राध्यापक मनोविज्ञान, डॉ. विजय लक्ष्मी गुप्ता प्राध्यापक दर्शनशास्त्र, डॉ. चंद्रकांत लवानिया प्राध्यापक विधि, डॉ. नरेंद्र सिंह राणा प्राध्यापक विधि।

शिक्षक का कोरोना से निधन, नगर में दूसरी और अंचल में पांचवी मौत

पीपुल्स संवाददाता ● भितरवार
editor@peoplessamachar.co.in

कोरोना की बीमारी से नगर के रहवासी शासकीय शिक्षक गिरजेश दिघर्रा का निधन हो गया। पिछले दिनों संक्रमित हुए शिक्षक श्री दिघर्रा ने इलाज के दौरान ग्वालियर के एक हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। जिसकी सूचना मिलते ही पूरे नगर में शोक की लहर दौड़ पड़ी। वहीं कोरोना से नगर में दूसरी और अंचल में हुई पांचवी मौत से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार नगर के वार्ड क्रमांक 12 में रहने वाले शासकीय माध्यमिक विद्यालय संजय नगर बागवई में पदस्त शिक्षक गिरजेश दिघर्रा पुत्र हरचरण लाल उम्र 48 वर्ष पिछले दिनों कोरोना संक्रमित पाए गए थे। जिन्हें इलाज में आराम न मिलने पर उनके परिजन ग्वालियर ले गए। जहां पीड़ित शिक्षक को सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसी बीच शुक्रवार को शिक्षक श्री दिघर्रा की हालत बिगड़ गई। और चिकित्सकों के प्रयासों के बीच शिक्षक ने अपना दम तोड़ दिया। जिस पर उनके परिजन उनके शव को लेकर भितरवार आए। जहां उन्होंने मुक्तिधाम में कोविड गाइड लाइन के तहत उनका अंतिम संस्कार किया। वहीं मिलनसार हंसमुख शिक्षक श्री दिघर्रा के निधन की सूचना मिलते ही पूरे नगर एवं क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। कोविड गाइड लाईन के तहत उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने से बंचित हुए लोगों ने शिक्षक की आत्म शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की। वहीं नगर में कोरोना से हुई दूसरी और अंचल में पांचवी मौत पर प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही लोगों में भी कोरोना को लेकर दहसत का माहौल पैदा हो गया है। उल्लेखनीय हैं। कि नगर में इससे पूर्व एक व्यवसायी कोरोना से निधन हो गया था। ग्राम चीनोर, ईटमा, ककरधा में भी कोरोना से तीन मौतें हो गईं।

पुराना बाजार मार्ग किया सील, आवाजाही बंद

पुराना बाजार वार्ड क्रमांक 12, 13 और 14 कोरोना हॉटस्पॉट बने हुए हैं। इन वार्डो में सर्वाधिक संक्रमित पाए गए हैं। वहीं कोरोना से एक व्यवसायी और एक शिक्षक की मौत गई हैं। इसके बाद सतर्क हुए स्थानीय निकाय द्वारा इन वार्डो की ओर जाने बाले मार्ग को सील कर दिया है। शुक्रवार को वार्ड क्रमांक 12 के रहवासी शिक्षक की कोरोना से हुई मौत की सूचना मिलते ही पहुँचे नगर परिषद के कर्मचारियों ने मेन तिराहे से पुराना बाजार की ओर जाने बाला मार्ग बेरिकेट्स लगाकर बंद कर दिया। जिससे इस मार्ग से आवाजाही बंद रहेगी।

आरजीपीवी: कोर्स पूरा कराने 6 दिन ऑनलाइन कक्षाएं लेना होंगी

- शिक्षक गूगल मीट के जरिए कक्षाएं ले रहे, वॉट्सएप पर भेज रहे नोट्स

पीपुल्स संवाददाता • ग्वालियर

editor@peoplessamachar.co.in

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विवि से संबद्ध पॉलीटेक्निक कॉलेजों में कोरोना के कारण भौतिक के बजाए ऑनलाइन कक्षाएं लग रही हैं। विवि ने कॉलेजों को सप्ताह में 6 दिन कक्षाएं लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं कि कोर्स समय पर पूरा कराया जा सके। कॉलेजों के शिक्षक गूगल मीट के जरिए छात्रों को पढ़ा रहे हैं साथ ही वॉट्सएप ग्रुप पर नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं। प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी वायवा के रूप में ली जा रही है। छात्र प्रैक्टिकल के वीडियो बनाकर भी भेज रहे हैं।

डिप्लोमा इंजीनियरिंग की परीक्षा 10 से, 9 को मॉक टेस्ट

आरजीपीवी डिप्लोमा इंजीनियरिंग फर्स्ट सेम के ऐसे छात्रों की परीक्षा 10 मई से फिर से कराने जा रहा है, जो अप्रैल में हुई ऑनलाइन परीक्षा में किसी कारण शामिल हुए नहीं हो पाए या अंक कम आए। परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, जिन छात्रों के रजिस्ट्रेशन हैं, उन्हें कराने की जरूरत नहीं है। विवि परीक्षा से एक दिन पहले यानि 9 मई को दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक मॉक टेस्ट कराने जा रहा है ताकि छात्रों को परीक्षा में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए।

भीमराव अंबेडकर कॉलेज में 50 फीसदी शिक्षक संक्रमित हैं

झांसी रोड स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर पॉलीटेक्निक कॉलेज में 40 शिक्षक हैं, इनमें 20-22 शिक्षक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और इलाज करा रहे हैं। कुछ शिक्षक कैंपस में रहते हैं, इनमें से कुछ शिक्षकों और उनके परिवार को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है, इसलिए शिक्षक डरे हुए हैं और घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं।

बिना एनसीटीई मान्यता के 15 कॉलेजों को संबद्धता देने पर आपत्ति

- विवि ने 200 से अधिक कॉलेजों को सत्र 21-22 की संबद्धता दी है

पीपुल्स संवाददाता • ग्वालियर

editor@peoplessamachar.co.in

जीवाजी विवि की कुलपति प्रो. संगीता शुक्ला की अध्यक्षता में 5 मई को ऑनलाइन हुई कार्यपरिषद की बैठक में बीएड, एमएड कोर्स चलाने वाले 200 से अधिक कॉलेजों को सत्र 2021-22 की संबद्धता दी गई है, इनमें से 15 कॉलेज ऐसे हैं, जिन्हें एनसीटीई से मान्यता नहीं होने के बाद भी नियमों की अवहेलना करके संबद्धता देने पर कार्यपरिषद सदस्य डॉ. मनेंद्र सिह सोलंकी और अनूप अग्रवाल कॉलेजों को संबद्धता देने के अलावा कई मुद्दों पर कुलपति और कुलसचिव नोट ऑफ डिसेंट दिया है।

इन पर भी आपत्ति है

डिप्लोमा एक्सरे के अध्यादेश के तहत एक साल में करने का नियम है मगर सत्र 14-15 के दो छात्रों को छह साल परीक्षा में शामिल किया गया, एमफिल क्लीनिकल सायकोलॉजी दो वर्षीय कोर्स में 8 सीट निर्धारित हैं, लेकिन सत्र 20-21 खत्म होने के बाद 4 छात्रों को नियम विरूद्ध प्रवेश दिया गया, शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए 8 क्रीड़ाधिकारियों से बीपीएड, एमपीएड के छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षक के तौर सेवाएं लेने पर आदि मुद्दों पर आपत्ति दर्ज कराई है।

इनका कहना है

विवि ने एनसीटीई कोर्स चलाने वाले 15 ऐसे कॉलेजों को संबद्धता दी है, जिन्हें एनसीटीई से मान्यता नहीं है। इस मुद्दे के अलावा अन्य मुद्दों को लेकर मैंने और मोनू ने नोट ऑफ डिसेंट दिया है।

अनूप अग्रवाल, ईसी मेंबर जेयू

आज आखिरी दिन, ऑनलाइन जानकारी नहीं दी तो 56 बीएड कॉलेज होंगे काउंसलिंग से बाहर

उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर के 591 कॉलेजों से मांगी थी जानकारी

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल
मो.नं. 9893231237

उच्च शिक्षा विभाग ने बीएड कॉलेजों में प्रवेश की तैयारियां पूरी कर ली हैं। विभाग ने एनसीटीई से मान्यता प्राप्त सभी 647 बीएड कॉलेजों से आठ मई तक ऑनलाइन डिटेल मांगी थी, लेकिन 56 कॉलेजों ने अभी तक जानकारी नहीं दी है। ऐसे मे यदि शनिवार तक जानकारी सबमिट नहीं होती है तो यह सभी कॉलेज काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे।

अभी तक आगामी सत्र 2021-22 में प्रवेश कराने के लिए विभाग तक 591 कॉलेज ही पहुंच सके हैं। गौरतलब है कि इस वक्त कोरोना संक्रमण तेजी से प्रदेश बढ़ रहा है। इसलिए विभाग ने अपनी सभी व्यवस्थाओं को ऑनलाइन

करने का निर्णय लिया है। इसके चलते विभाग ने प्रदेश के सभी बीएड कॉलेजों में प्रवेश कराने संबंधित सभी गतिविधियों को ऑनलाइन कर दिया है। विभाग ने कॉलेजों को सत्र 2021-22 में प्रवेश कराने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाते हुए उनसे आठ मई तक सभी जानकारी पोर्टल के माध्यम से भेजने के निर्देश दिए थे। इसमें अब तक प्रदेश 591 कॉलेजों ने ही भागीदारी की है। अभी भी 56 कॉलेजों ने प्रवेश देने के लिए कोई जानकारी नहीं दी है।

विवि द्वारा जांच पूरी होने पर ही मिलेगी कोर्स की मान्यता

अभी तक उच्च शिक्षा विभाग कॉलेजों के समस्त प्रकार के दस्तावेजों को देखने के लिए कमेटी द्वारा कराता था। लेकिन, कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ने के मद्देनजर उच्च शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाया है। इस प्रक्रिया के चलते कालेजों द्वारा पोर्टल पर दी गई जानकारी को विवि पहले संबद्धता देते हुए ओके करेगा। इसके बाद उच्च शिक्षा विभाग कॉलेजों के एनसीटीई से कोर्स की मान्यता और प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति द्वारा फीस निर्धारित कराने के पत्र का परीक्षण करेगा। इसके बाद ही उच्च शिक्षा विभाग ऐसे कॉलेजों को आन लाइन काउंसिलिंग में शामिल होने की पात्रता प्रदान करेगा।

भोपाल के साइकोलॉजिस्ट ने शुरू की पॉजिटिव थॉट्स मुहिम, कहा- निगेटिव खबरें व कोरोना का डर कम करता है मरीज की रिकवरी

अध्ययन में खुलासा : सकारात्मक विचारों से बढ़ती है इम्युनिटी

पल्लवी वाघेला ● भोपाल
मो.नं. 9827229058

पॉजिटिव थॉट्स व आत्मबल से कोरोना जैसी बीमारी को आसानी से हराया जा सकता है, वहीं डर व निगेटिव खबरें मरीज की इम्युनिटी घटा देती हैं। कोरोना संक्रमित व्यक्ति का रिकवरी रेट धीमा हो जाता। कई बार तो मरीज मौत के कगार तक पहुंच जाता है। मानसिक समस्याओं से जुड़ी देश की प्रतिष्ठित संस्था इंडियन साइकेट्रिक सोसायटी (आईपीएस) के साथ ही कुछ अन्य संस्थाओं द्वारा की गई केसेस की स्टडी में यह बात सामने आई है। स्टडी के मुताबिक 1,685 लोगों में से 10.5% गंभीर डिप्रेशन व डर का शिकार थे, इस वजह से वे मौत के कगार तक पहुंच गए। वहीं 5% ने गंभीर अवस्था के बाद भी पॉजिटिव एप्रोच व इच्छा शक्ति से संक्रमण को मात दी।

पीपुल्स समाचार
वीकेंड स्पेशल

शुरू की पॉजिटिव मैसेज भेजने की मुहिम: भय का माहौल कम करने के लिए शहर के साइकोलॉजिस्ट पॉजिटिव मैसेज भेज रहे हैं। इस मुहिम में आम लोग भी शामिल हो रहे हैं। कुछ लोगों ने दिन में कम से कम 20 लोगों को पॉजिटिव मैसेज भेजने का लक्ष्य रखा है। साथ ही निगेटिव मैसेज व मृत्यु संबंधी जानकारी शेयर करना भी बंद कर दी है।

IPS के 650 मनोरोग विशेषज्ञों ने कोरोना से रिकवरी होने वाले मरीजों पर स्टडी में किया खुलासा

74% में मॉडरेट स्तर का अवसाद
10.5% गंभीर डिप्रेशन से पीड़ित
9.5% में डिप्रेशन पाया गया
5% गंभीर बीमार थे, उन्होंने पॉजिटिविटी के कारण कोरोना को हराया

खुद को स्वस्थ रखना है तो खुश रहें व जिससे भी बात करें अपनी बातचीत में सकारात्मकता रखें। डर इम्युनिटी को घटाती है। पॉजिटिव मैसेजेस पर हमारा फोकस है। मेरे पास कुछ केसेस में फास्ट रिकवरी भी हुई है।

– दिव्या दुबे मिश्रा, मनोवैज्ञानिक

लोगों में डर की बजाए सामना करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। हमारी कोशिश है लोगों को पॉजिटिव एनर्जी दें। इसके लिए पर्सनल बातचीत, मैसेज व वीडियो मैसेज के जरिए हम पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करने में लगे हैं।

– डॉ. दीप्ति सिंघल, मनोवैज्ञानिक

कोरोना पॉजिटिव दोस्त को रोज पॉजिटिव मैसेज भेजती थी। उसने कहा इससे मेरा आत्मविश्वास बना रहता है। इसके बाद से मैं रोज 50 लोगों को सोशल मीडिया माध्यम से इस तरह के मैसेज भेज रही हूं। खासकर अपने परिचित कोविड पेशेंट को। मैंने शोक संदेश शेयर करना बंद कर दिया है।

– शिवी खरे, स्टूडेंट

DBStar PUBLIC TALK - परीक्षा की गुणवत्ता और डिग्री की विश्वसनीयता बनाए रखना बहुत जरूरी है

हालात बेहतर होने पर परीक्षाएं ऑफलाइन सिस्टम से ही होना चाहिए

इंदौर | DBStar

विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर स्थिति साफ नहीं हो रही है। डीएवीवी की फाइनल ईयर की परीक्षाएं जून में ओपन बुक सिस्टम से होंगी, जबकि अन्य परीक्षा जुलाई में होने की बात कही गई है। पिछले साल ओपन बुक सिस्टम के तहत हुई परीक्षाओं को लेकर कई विसंगतियां सामने आई थीं। अधिकांश लोगों का मत है कि ऑफलाइन एक्जाम ही होना चाहिए, लेकिन फिलहाल नहीं। जब तक हालात बेहतर नहीं हो जाते हैं तब तक सभी परीक्षाएं टाल दी जाएं।

कुछ दिनों के लिए परीक्षाएं स्थगित करना ही सही विकल्प

वैसे तो ऑफलाइन परीक्षा ही बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी की वास्तविक कुशलता का पता चलता है,

लेकिन संकट दौर में परीक्षाएं कुछ दिनों की स्थगित की जा सकती हैं। ऑनलाइन एग्जाम में विद्यार्थी किस तरह एग्जाम दे रहा है, यह नहीं पता लगाया जा सकता है। मौजूदा हालात में परीक्षाएं कुछ दिन के लिए स्थगित करना ही सही विकल्प है।

मीनू कटारिया, गृहिणी

छात्रों को प्रश्न पत्र की लिंक दी जाए और वह तय अवधि में उत्तर दें

कोरोना संक्रमण के कारण ऑनलाइन परीक्षा ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। ऑनलाइन परीक्षा के लिए सॉफ्टवेयर की मदद से प्रश्न पत्रों

को लिंक के माध्यम से विद्यार्थियों के मेल, वाट्सएप या महाविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाए, जिससे निश्चित समय पर लिंक ओपन हो और निर्धारित अवधि में बंद हो जाए। इस अवधि में वह अपना उत्तर सबमिट कर दें। इससे मूल्यांकन में भी पारदर्शिता रहेगी।

डॉ. वंदना श्रीवास्तव, सह प्राध्यापक

संसाधन नहीं, ऑनलाइन परीक्षा सभी छात्र नहीं दे सकते

ऑफलाइन परीक्षाएं कराना स्वास्थ्य की दृष्टि से गलत हैं। ऑनलाइन परीक्षा अच्छा विकल्प है, लेकिन बहुत से छात्र ऑनलाइन

परीक्षा देने में असमर्थ हैं। उनके पास एंड्राइड फोन नहीं है या फिर नेटवर्क की समस्या है। ऐसे में पिछले वर्ष के अंक के आधार पर छात्रों आकलन कर वर्तमान वर्ष का परिणाम घोषित कर सकते हैं। सही समय पर रिजल्ट आने से छात्र बेहतर तरीके से भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं।

अजीतकुमार पटेल, रिक्रूटमेंट मैनेजर

बिना तैयारी के ऑनलाइन परीक्षाएं लेना सही हल नहीं

कोरोना काल में यूरोप व अमेरिका में पूरा एग्जाम सिस्टम ऑनलाइन मोड पर कर दिया गया, पर हमारे यहां ऑनलाइन एजुकेशन

व एग्जाम सीमित है। महामारी के दौर में ऑफलाइन एग्जाम नहीं कराई जा सकती है, पर केवल शैक्षणिक सत्र के समाप्त होने पर बिना तैयारी के ऑनलाइन एग्जाम लेना समस्या का हल नहीं है। एग्जाम की क्वालिटी और डिग्री की विश्वसनीयता से समझौता नहीं करना चाहिए।

डॉ. रवींद्र पाठक, एसोसिएट प्रोफेसर

लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के कारण पिछले साल यूनिवर्सिटी की कुछ परीक्षाएं ऑफलाइन हुईं, कुछ ऑनलाइन तो कुछ ओपन बुक सिस्टम से। इस बार तो परीक्षाएं शुरू ही नहीं हुई हैं। साथ ही संक्रमितों मरीजों की संख्या भी पिछले साल मुकाबले करीब तीन गुना ज्यादा है। ऐसे में विद्यार्थियों के साथ ही उनके अभिभावक भी चिंतित हैं कि परीक्षा किस तरह होगी। इस बार का विषय 'परीक्षाएं ऑफलाइन हों या ऑनलाइन।' पाठक अपने विचार 100 शब्दों (हिंदी) में फोटो सहित 9926088440 पर वाट्सएप कर सकते हैं।

आज का इतिहास

- 1360: अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने ब्रिटिग्नी समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- 1541: हर्नांडो डे सोटो ने मिसीसिपी नदी की खोज की।
- 1777: बंगाल के नवाब मीर कासिम का निधन।
- 1847: रॉबर्ट डब्ल्यू. थॉम्पसन ने रबर टायर का पेटेंट करवाया।
- 1871: ब्रिटेन-अमेरिका के बीच समझौते के बाद अलबामा विवाद समाप्त हुआ।
- 1886: कोल्ड-ड्रिंक कोकाकोला का उत्पादन शुरू हुआ।
- 1895: प्रसिद्ध क्रांतिकारी गोपबन्धु चौधरी का जन्म।
- 1921: स्वीडन ने फांसी की सजा को खत्म किया।
- 1926: प्रसिद्ध हिन्दी नायिका निरूपा रॉय का जन्म।
- 1933: महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ 21 दिन का उपवास रखा।

आज का इतिहास

1929 गिरिजा देवी - भारत की प्रसिद्ध ठुमरी गायिका का जन्म हुआ।

1916 स्वामी चिन्मयानंद - भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक चिंतक तथा वेदान्त दर्शन के विश्व प्रसिद्ध विद्वान का जन्म हुआ।

1895 गोपबन्धु चौधरी - उड़ीसा के प्रसिद्ध क्रांतिकारी तथा सामाजिक कार्यकर्ता का जन्म हुआ।

1982 [illegible] रामजी देशपांडे - प्रसिद्ध मराठी साहित्यकार का निधन हुआ।

1945 मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के समक्ष जर्मनी का आत्मसमर्पण।

1980 कोलकाता स्थित चीनी दूतावास पर नक्सलियों द्वारा पेट्रोल बमों से हमला।

2000 भारतीय मूल के 69 वर्षीय लॉर्ड स्वराजपाल ब्रिटेन के चौथे सबसे बड़े विश्वविद्यालय ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के कुलपति नियुक्त।